भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या:2498
13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा अवसंरचना

2498. श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवाओं, उपकरणों, डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और तकनीशियनों की वास्तविक उपलब्धता और घोषित उपलब्धता के बीच के अंतर का ब्यौरा क्या है
(ख) क्या देवरिया जिले में एक सदर अस्पताल की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऐसा प्रस्ताव लाने के लिए यदि कोई समय सीमा है, तो उसका ब्यौरा क्या है,
(घ) बलिया में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पूरा होने और इसके कार्याशील होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है
(ङ) देवरिया, बलिया और उत्तर प्रदेश के अन्य जिला अस्पतालों में चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा के रिक्त पदों की संख्या कितनी है तथा इन्हें भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(च) अस्पताल प्रब्रंधन, पारदर्शिता, शिकायत निवारण और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य विषय हैं और डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों के रिक्त पदों के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में उपकरणों और निदान अवसंरचना को मजबूत करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने समग्र संसाधन आवंटन के भीतर प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रस्ताव को कार्यवाही के अभिलेख (आरओपी) के रूप में मंजूरी प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला अस्पतालों और उससे निचले स्तर के सुविधा केंद्रों में डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मचारियों और तकनीशियनों की उपलब्धता से संबंधित विवरण, हेल्थ डायनामिक्सऑफ इंडिया (इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज) 2022-23 रिपोर्ट में निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है।

https://www.mohfw.gov.in/?q=en/reports-23

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, दवाओं की वास्तविक उपलब्धता और घोषित उपलब्धता का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.स.	स्वास्थ्य सुविधा केंद्र	सरकार द्वारा अनुमोदित/घोषित कुल दवाएं (ईडीएल)	दवा की दुकानों में उपलब्ध दवाइयाँ
1	जिला अस्पताल	394	324
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी)	242	214
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / स्वास्थ्य एवं कल्याण पीएचसी (ए.ए.एम. पीएचसी)	195	181
4	स्वास्थ्य एवं कल्याण उप-केंद्र (ए.ए.एम.)	84	79

उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आरंभ किए गए या कार्यशील स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण, परियोजना-वार और वर्ष-वार बजट अनुमोदन, मंत्रालय की वेबसाइट पर कार्यवाही के अभिलेखों में निम्नलिखित लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=49&lid=62

(घ) और (ङ): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, राज्य के जिला अस्पतालों में एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 3,123 है, जिनमें से 2,002 पद वर्तमान में भरे हुए हैं। देवरिया जिले में, 167 स्वीकृत पदों में से 135 चिकित्सा अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं। इसी प्रकार, बलिया जिले में, 277 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 190 चिकित्सा अधिकारी पदस्थ हैं।

(च): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, एनएचएम सेवाओं, योजनाओं, कर्मियों और अन्य संबंधित मामलों से संबंधित शिकायतों और समस्याओं को दूर करने के लिए एक संरचित तंत्र तैयार किया गया है। यह उत्तर प्रदेश सहित भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में जवाबदेही, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सेवा प्रदायगी में

सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) एनएचएम के अंतर्गत एक गुणवत्ता आश्वासन पहल है, जिसे उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है।

******